प्रारंभिक परीक्षा

शिमला समझौता (1972)

संदर्भ:

शिमला समझौते (Simla Agreement) के 54 वर्ष पूरे हो गए हैं।

शिमला समझौते (1972) के बारे में

- **1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को इस पर हस्ताक्षर किए गए।**
- भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
- **उद्देश्य:** स्थायी शांति स्थापित करना और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाना।
- दोनों देश बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के, द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सभी विवादों को सुलझाने पर सहमत हुए।
- जम्मू-कश्मीर में युद्धविराम रेखा (Ceasefire line) को नियंत्रण रेखा (Line of Control - LoC) के रूप में फिर से नामित किया गया, जिसमें दोनों पक्ष एकतरफा रूप से इसे नहीं बदलने पर सहमत हुए।

मानस (MANAS) पहल

संदर्भ:

मानस (MANAS) पहल नागरिकों को नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाकर मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ भारत के प्रयासों को मजबूत कर रही है।

मानस पहल के बारे में

- **मानस (MANAS - मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र) राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था।**
- **कार्यान्वयन:** डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के सहयोग से गृह मंत्रालय (MHA) के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा।
- यह निम्नलिखित के लिए एक प्रौद्योगिकी-सक्षम मंच है:
    - मादक पदार्थों (ड्रग्स) से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग।
    - परामर्श (counselling) प्राप्त करना।
    - नशामुक्ति और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच।
- **पहुंच का माध्यम:** हेल्पलाइन 1933, आधिकारिक पोर्टल, ईमेल और उमंग (UMANG) ऐप के माध्यम से।

चाल विश्लेषण (GAIT ANALYSIS)

संदर्भ:

हाल ही में पुणे के एक हत्या के मामले में, जांचकर्ताओं ने संदिग्धों की पहचान करने में मदद के लिए फोरेंसिक 'चाल विश्लेषण' (Gait analysis) का उपयोग किया।

चाल विश्लेषण के बारे में

- चाल विश्लेषण (Gait analysis) मानव गति (locomotion), विशेष रूप से चलने और दौड़ने का वैज्ञानिक अध्ययन है।
- यह गति के दौरान मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों और तंत्रिका तंत्र के समन्वय (coordination) की जांच करता है।
- प्रत्येक व्यक्ति की एक विशिष्ट चाल (gait pattern) होती है, जो बायोमेट्रिक पहचानकर्ता के रूप में कार्य कर सकती है।
- **अनुप्रयोग:** फोरेंसिक जांच, खेल विज्ञान, पुनर्वास और चिकित्सा निदान में उपयोग किया जाता है।

मेकॉन लिमिटेड और मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा (MECON LIMITED & MINIRATNA CATEGORY-I STATUS)

संदर्भ:

इस्पात मंत्रालय ने मेकॉन लिमिटेड (MECON Limited) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान किया है।

मिनीरत्न दर्जे के बारे में

- सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को प्रदान किया जाता है।
- **शुरुआत:** 1997 में अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करने के लिए।
- श्रेणी-I और श्रेणी-II में वर्गीकृत किया गया है।

पात्रता मानदंड

- **श्रेणी-I:** पिछले 3 लगातार वर्षों में लाभ, उन वर्षों में से किसी एक में कम से कम ₹30 करोड़ का कर-पूर्व लाभ (pre-tax profit), और सकारात्मक निवल मूल्य (positive net worth)।
- **श्रेणी-II:** पिछले 3 लगातार वर्षों में लाभ और सकारात्मक निवल मूल्य।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP)

संदर्भ:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) के बारे में

- बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने वाला भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार।

- **प्रदाता:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल नई दिल्ली में वीर बाल दिवस (26 दिसंबर) पर प्रदान किया जाता है।
- **पात्रता:** 5-18 वर्ष की आयु के बच्चे।
- **पुरस्कार श्रेणियाँ (6):** बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
- **नामांकन:** नागरिकों, स्कूलों, संस्थानों, संगठनों द्वारा या स्व-नामांकन के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- **पुरस्कार में शामिल हैं:** एक पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।

वीर बाल दिवस

- **मनाया जाता है:** हर साल 26 दिसंबर को।
- 10वें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद दिलाता है।
- साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सरहिंद के मुगल गवर्नर वज़ीर खान के आदेश पर उन्हें सरहिंद में शहीद कर दिया गया था।
- उन्होंने अपना धर्म छोड़ने के बजाय शहादत को चुना, जो साहस, बलिदान और अटूट विश्वास का प्रतीक है।

माचा चाय (MATCHA TEA)

संदर्भ:

असम के छोटा टिंगराई चाय बागान ने व्यावसायिक रूप से उगाई गई भारत की पहली 'माचा चाय' (Matcha tea) का उत्पादन और बिक्री की है।

माचा चाय के बारे में

- **माचा एक बारीक पीसी हुई ग्रीन टी (green tea) है जो कैमेलिया साइनेंसिस (Camellia sinensis) की छाया में उगाई गई पत्तियों से बनी होती है।**
- नियमित ग्रीन टी के विपरीत, इसमें पूरे चाय पाउडर का सेवन किया जाता है, जो उच्च स्तर के एंटीऑक्सिडेंट, पोषक तत्व और कैफीन प्रदान करता है।
- **उत्पत्ति:** यह प्रथा सोंग राजवंश (Song Dynasty) के दौरान चीन में उत्पन्न हुई और 12वीं शताब्दी में ज़ेन भिक्षु आइसाई (Eisai) द्वारा इसे जापान लाया गया, जहाँ यह पारंपरिक जापानी चाय संस्कृति में विकसित हुई।
- कटाई से 3-4 सप्ताह पहले चाय के पौधों को छाया में उगाया जाता है, जिससे क्लोरोफिल और एल-थेनाइन (L-theanine) बढ़ता है, जो चाय के चमकीले हरे रंग और उमामी (umami) स्वाद को बढ़ाते हैं।
- चीन दुनिया का सबसे बड़ा माचा उत्पादक है।

लोकओएस प्लेटफॉर्म (LOKOS PLATFORM)

संदर्भ:

लोकओएस (LokOS) प्लेटफॉर्म का पूरे भारत में विस्तार हुआ है, जिससे स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और अन्य सामुदायिक संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन में तेजी आई है।

लोकओएस प्लेटफॉर्म के बारे में

- **लोकओएस (LokOS - लोक = लोग; ओएस = ऑपरेटिंग सिस्टम) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत एक वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म है।**
- यह स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों (VOs), क्लस्टर स्तर के संघों (CLFs) और उनके सदस्यों के प्रबंधन के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्रणाली प्रदान करता है।
- यह आधार (Aadhaar) और बैंक-लिंक्ड डिजिटल आईडी उत्पन्न करता है तथा बचत, ऋण, पुनर्भुगतान और अन्य वित्तीय लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड रखता है।

विशेष निवेश कोष (SPECIALISED INVESTMENT FUND - SIF)

संदर्भ:

विशेष निवेश कोषों (SIFs) ने तीव्र वृद्धि देखी है, और उनके प्रबंधन के अधीन संपत्तियां (AUM) ₹13,814 करोड़ को पार कर गई हैं।

विशेष निवेश कोष (SIF) के बारे में

- **SIF भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा पेश किया गया एक नया निवेश उत्पाद है।**
- म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (PMS) के बीच के अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया।
- **न्यूनतम निवेश:** ₹10 लाख प्रति निवेशक।
- यह ओपन-एंडेड (open-ended), क्लोज-एंडेड (close-ended) या अंतराल-आधारित (interval-based) हो सकता है।
- **निवेश रणनीतियाँ:** इक्विटी-उन्मुख, ऋण-उन्मुख (Debt-oriented) और हाइब्रिड।

एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के लिए पात्रता

- **मार्ग 1 (Route 1):** पिछले तीन वर्षों में ₹10,000 करोड़ के औसत AUM के साथ कम से कम 3 साल का संचालन।
- **मार्ग 2 (Route 2):** ₹5,000 करोड़ से अधिक के AUM के प्रबंधन के 10+ वर्षों के अनुभव वाले एक मुख्य निवेश अधिकारी (CIO) की नियुक्ति, साथ ही ₹500 करोड़ से अधिक के AUM के प्रबंधन के 3+ वर्षों के अनुभव वाले एक अतिरिक्त फंड मैनेजर की नियुक्ति।

नामेरी टाइगर रिज़र्व (NAMERI TIGER RESERVE)

संदर्भ:

असम के नामेरी टाइगर रिज़र्व में पिछले तीन वर्षों में बाघों की आबादी चौगुनी हो गई है।

नामेरी टाइगर रिजर्व के बारे में

- **स्थान:** असम; अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिज़र्व (Pakke Tiger Reserve) के साथ अपनी उत्तरी सीमा साझा करता है।
- **प्रमुख नदियाँ:** जिया भोरोली (Jia Bhoroli)।
- जिया भोरोली नदी 'गोल्डन महसीर' मछली के लिए प्रसिद्ध है, जिसे "भारतीय नदियों का बाघ" भी कहा जाता है।

मुख्य परीक्षा

भारत में क्विक कॉमर्स (QUICK COMMERCE) का उदय

संदर्भ:

क्विक कॉमर्स हाइपर-लोकल डिलीवरी और डिजिटल नवाचार के माध्यम से भारत के खुदरा परिदृश्य को तेजी से बदल रहा है। हालांकि यह उपभोक्ता सुविधा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है, यह प्रतिस्पर्धा, किराना स्टोर और गिग-वर्कर्स के कल्याण को लेकर भी चिंताएं पैदा करता है, जो एक संतुलित विनियामक ढांचे की आवश्यकता को उजागर करता है।

भारत में क्विक कॉमर्स के विकास से जुड़े प्रमुख अवसर क्या हैं?

- **शहरी खुदरा व्यापार में परिवर्तन:** क्विक कॉमर्स दैनिक आवश्यक वस्तुओं तक त्वरित पहुंच को सक्षम करके, और तेजी से समय-बाधित होती जीवन शैली का समर्थन करके शहरी खपत को नया आकार दे रहा है।
    - उदाहरण के लिए: ब्लिंकिट (Blinkit), जेप्टो (Zepto) और स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) जैसे प्लेटफार्मों ने किराने के सामान, दवाओं और घरेलू आवश्यक वस्तुओं की लगभग-तत्काल डिलीवरी को मुख्यधारा में ला दिया है।
- **प्लेटफॉर्म-आधारित रोजगार का सृजन:** क्विक कॉमर्स के तीव्र विस्तार ने डिलीवरी भागीदारों, गोदाम कर्मियों और रसद (लॉजिस्टिक्स) श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जो भारत की प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए: नीति आयोग का अनुमान है कि 2029-30 तक भारत का गिग कार्यबल (gig workforce) 23.5 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं की एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी।
- **प्रौद्योगिकी और रसद नवाचार में तेजी:** यह क्षेत्र एआई-संचालित (AI-driven) मांग पूर्वानुमान, भविष्य कहनेवाला इन्वेंट्री प्रबंधन (predictive inventory management), और माइक्रो-फुलफिलमेंट नेटवर्क में निवेश बढ़ा रहा है, जिससे भारत की रसद क्षमताओं को मजबूती मिल रही है।
    - उदाहरण के लिए: जेप्टो इन्वेंट्री और डिलीवरी मार्गों को अनुकूलित (optimise) करने के लिए एआई (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है।
- **हाइपरलोकल आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना:** सघन डार्क-स्टोर नेटवर्क लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स में सुधार करते हैं और आपात स्थिति के दौरान आवश्यक वस्तुओं के तेजी से वितरण को बढ़ाते हैं।
    - उदाहरण के लिए: क्विक-कॉमर्स प्लेटफार्मों ने कोविड-19 महामारी और 2024 के बेंगलुरु जल संकट के दौरान आवश्यक डिलीवरी का समर्थन किया।
- **स्टार्टअप और निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना:** क्विक कॉमर्स उद्यम पूंजी (venture capital) के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है, जो खुदरा प्रौद्योगिकी और रसद में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
    - उदाहरण के लिए: व्यापक स्टार्टअप फंडिंग में मंदी के बावजूद जेप्टो ने यूनिकॉर्न (unicorn) का दर्जा हासिल किया।

- **एक प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था का निर्माण:** खुदरा व्यापार से परे, क्विक कॉमर्स डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है जहां रसद, उपभोक्ता डेटा और खुदरा मीडिया मूल्यवान आर्थिक संपत्ति बन जाते हैं।
- **महानगरों से परे भविष्य का विस्तार:** जैसे-जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे और क्रय शक्ति में सुधार होता है, त्वरित वाणिज्य (क्विक कॉमर्स) में क्षेत्र-विशिष्ट व्यापार मॉडल के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों में विस्तार करने की क्षमता है।

क्विक कॉमर्स परिदृश्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **गिग अर्थव्यवस्था में श्रम अनिश्चितता (Labour Precarity):** एल्गोरिदम-संचालित प्रदर्शन लक्ष्यों के बावजूद प्लेटफॉर्म-आधारित डिलीवरी कार्य में अक्सर स्थिर आय, औपचारिक रोजगार संरक्षण और व्यापक सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है।
- **स्वतंत्र खुदरा व्यापार पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव:** प्लेटफॉर्म का पैमाना, रसद दक्षता और मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ आस-पड़ोस के किराना स्टोरों और अन्य स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ाती हैं। a. उदाहरण के लिए: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने शहरी किराना स्टोरों के बीच घटती बिक्री को उजागर किया है।
- **प्लेटफॉर्म का संकेंद्रण और ऊर्ध्वाधर एकीकरण (Vertical Integration):** एल्गोरिदम, उपभोक्ता डेटा और पसंदीदा-विक्रेता (preferred-seller) नेटवर्क पर बढ़ता नियंत्रण प्लेटफॉर्मों को बाजार पहुंच को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है, जबकि वे निजी लेबल (private labels) के माध्यम से तृतीय-पक्ष विक्रेताओं (third-party sellers) के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- **शहरी बुनियादी ढांचा और पर्यावरणीय बाह्यताएं (Environmental Externalities):** उच्च-आवृत्ति वाली डिलीवरी से भीड़भाड़, पैकेजिंग अपशिष्ट और अंतिम-मील (last-mile) उत्सर्जन में वृद्धि होती है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। a. उदाहरण के लिए: बड़ी डिलीवरी फ्लीट बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में भीड़भाड़ (congestion) में योगदान करती हैं।
- **महानगर-केंद्रित विकास मॉडल:** डार्क स्टोर्स के अर्थशास्त्र के लिए उच्च जनसंख्या घनत्व और बार-बार ऑर्डर करने की आवश्यकता होती है, जो कई टियर-2 और टियर-3 शहरों में इसके तीव्र विस्तार को सीमित करता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण और विनियामक कमियां:** मूल्य निर्धारण पारदर्शिता, उत्पाद की गुणवत्ता और शिकायत निवारण के लिए समर्पित मानकों का अभाव जवाबदेही संबंधी चुनौतियां पैदा करता है।

आगे की राह

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और प्लेटफॉर्म तटस्थता (Platform Neutrality) सुनिश्चित करना** प्रतिस्पर्धा नीति को समान अवसर (level playing field) को संरक्षित करते हुए प्रमुख प्लेटफार्मों को प्रीडेटरी प्राइसिंग (predatory pricing - बहुत कम मूल्य निर्धारण), स्व-प्राथमिकता (self-preferencing), एल्गोरिथम भेदभाव, और प्रतिस्पर्धा-विरोधी ऊर्ध्वाधर एकीकरण के माध्यम से बाजार की शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना चाहिए।

- उदाहरण के लिए: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा प्रवर्तन को मजबूत करना, जिसमें पसंदीदा-विक्रेता व्यवस्थाओं (preferred-seller arrangements) और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग की तेजी से जांच शामिल हो।

- **प्लेटफॉर्म वर्करों के लिए एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करना** गिग वर्करों को पारंपरिक कर्मचारियों के रूप में फिर से वर्गीकृत करने के बजाय, भारत को श्रम-बाजार के लचीलेपन को बनाए रखते हुए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), 2020 के तहत मौजूदा ढांचे को मजबूत करना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए: पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, एल्गोरिथम पारदर्शिता, और प्लेटफॉर्म-वित्तपोषित कल्याणकारी योगदान प्रदान करना जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती हो और श्रमिकों, उपभोक्ताओं या छोटे विक्रेताओं पर अत्यधिक लागत के बोझ (cost pass-through) को कम करने के लिए पारदर्शी रूप से कैलिब्रेट किया जाता हो।
- **विश्वसनीय डिजिटल बाज़ारों का निर्माण करना** मजबूत डेटा प्रशासन (डेटा गवर्नेंस), पारदर्शी मूल्य निर्धारण और कुशल शिकायत निवारण के माध्यम से उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करना।
    - उदाहरण के लिए: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करना, साथ ही पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रकटीकरण (disclosures), मानकीकृत रिफंड नीतियां, और समयबद्ध ऑनलाइन विवाद समाधान सुनिश्चित करना।
- **समावेशी डिजिटल वाणिज्य को बढ़ावा देना** अंतर-संचालनीय (interoperable) डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से एमएसएमई (MSMEs), किराना स्टोर और स्थानीय उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार पहुंच का विस्तार करना।
    - उदाहरण के लिए: डिजिटल क्षमता-निर्माण, रसद (लॉजिस्टिक्स) सहायता और कार्यशील पूंजी तक आसान पहुंच के साथ-साथ डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) का विस्तार करना।
- **संधारणीय (Sustainable) शहरी लॉजिस्टिक्स को सक्षम करना** रसद मॉडल में नवाचार की अनुमति देते हुए उच्च-आवृत्ति वाली डिलीवरी की पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचा लागतों को आंतरिक बनाना (Internalise)।
    - उदाहरण के लिए: परिणाम-आधारित पर्यावरणीय मानकों के माध्यम से ईवी (EV) आधारित डिलीवरी फ्लीट, टिकाऊ पैकेजिंग और डार्क स्टोर्स की वैज्ञानिक ज़ोनिंग को बढ़ावा देना।